



लोक सभा सचिवालय  
प्रेस एवं जन सम्पर्क स्कंध  
संसद भवन, नई दिल्ली  
**LOK SABHA SECRETARIAT**  
Press and Public Relations Wing  
Parliament House, New Delhi

## प्रेस विज्ञप्ति PRESS RELEASE

लोक सभा अध्यक्ष ने शिलांग में मेघालय और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों के स्थानीय निकायों के लिए आउटरीच और परिचय कार्यक्रम का उद्घाटन किया

....

लघु विधायी निकायों के रूप में कार्य करने वाली जिला परिषदों को कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए : लोक सभा अध्यक्ष

...

एकट ईस्ट नीति से उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाओं के द्वार खुले हैं : श्री ओम बिरला

...

श्री बिरला ने स्थानीय निकायों के प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए सूचना और संचार तकनीकों तथा नई प्रौद्योगिकियों का अधिकाधिक उपयोग किए जाने पर बल दिया

...

लोक सभा अध्यक्ष ने लोकतांत्रिक संस्थाओं के सभी भागीदारों से सकारात्मक चर्चा और संवाद के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान करने का आग्रह किया

...

हमें अपने विचारों और कार्यों में राष्ट्रीय एकता के मूलभूत आदर्श को प्राथमिकता देनी चाहिए : मुख्य मंत्री, मेघालय

शिलांग 26 फरवरी 2021: लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला 25 फरवरी 2021 को शिलांग पहुंचे और आज उन्होंने मेघालय और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों के स्थानीय निकायों के लिए आउटरीच और परिचय कार्यक्रम का उद्घाटन किया ।

मेघालय के मुख्य मंत्री, डॉ कॉनरेड के संगमा; केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री, रामेश्वर तेली; मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष, श्री मेतबाह लिंगदोह; मेघालय सरकार के जिला परिषद कार्य विभाग मंत्री, श्री लखमन रिम्बुई भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए ।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्यपालिका की जवाबदेही केवल संसद और विधान सभाओं में ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर भी सुनिश्चित की जाए । इस संबंध में श्री बिरला ने इस बात पर बल दिया कि लघु विधायी निकायों के रूप में कार्य करने वाली स्वायत्त जिला परिषदों को चर्चा और संवाद के माध्यम से कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए ।

श्री बिरला ने कहा कि 'वोकल फॉर लोकल' जैसी पहलों से स्थानीय क्षेत्रों का विकास होगा । उन्होंने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब हम वोकल फॉर लोकल का चुनाव करेंगे । महात्मा गांधी की संकल्पना का स्मरण करते हुए, लोक सभा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर होगा, तभी भारत आत्मनिर्भर होगा । अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि हमारी एक्ट ईस्ट नीति से उत्तर- पूर्व क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाओं के द्वार खुले हैं और उत्तर पूर्वी राज्यों को इन अवसरों का अधिकाधिक लाभ उठाना चाहिए।

श्री बिरला ने स्थानीय निकायों के प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सुगम बनाने के लिए सूचना और संचार तकनीकों और नई प्रौद्योगिकियों के अधिकाधिक उपयोग पर बल दिया । अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि पंचायती राज संस्थाएं समावेशी विकास की अवधारणा के साथ विकास कार्यक्रमों के संबंध में सहयोग और सामूहिकता की भावना से चर्चा करे तथा जनता की समस्याओं का समाधान जनता को केन्द्र में रखकर निकालें।

क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री बिरला ने कहा कि हमारे लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं । उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं के भागीदारों से सकारात्मक चर्चा और संवाद के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान करने का आग्रह किया ।

यह टिप्पणी करते हुए कि हमें अपने विचारों और कार्यों में राष्ट्रीय एकता के मूलभूत आदर्श को प्राथमिकता देनी चाहिए, मेघालय के मुख्य मंत्री, डॉ कॉनरेड के संगमा ने वित्त

आयोग अंतरण के अंतर्गत जिला परिषदों का वित्तपोषण किए जाने; जिला परिषदों को दल-बदल विरोधी कानून के अंतर्गत लाए जाने; खासी, गारो और अन्य भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने; उत्तर-पूर्वी जनजातियों और संस्कृति संबंधी जानकारी को स्कूली बच्चों के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने; और उत्तर-पूर्व में राष्ट्रपति आवास स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन शिलांग में किए जाने तथा मेघालय और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्रदान करने के लिए लोक सभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री, श्री रामेश्वर तेली ने कहा कि पंचायत राज संस्थाएं और अन्य स्थानीय निकाय राष्ट्र-निर्माण के शक्तिशाली माध्यम हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जमीनी स्तर पर लोकतान्त्रिक प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए लोकतन्त्र के परंपरागत मूल्यों का संरक्षण किया जाना चाहिए।

मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष, श्री मेतबाह लिंगदोह ने स्व-शासन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि इससे न केवल आम जनता सशक्त होगी बल्कि शासन को समाज के अंतिम व्यक्ति के द्वार तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने निचले स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं और स्वायत्त जिला परिषदों को सशक्त किए जाने पर जोर दिया ताकि ऐसे निकायों की चर्चाओं में लोगों की शिकायतों और आकांक्षाओं पर भी विचार किया जा सके।

मेघालय सरकार के जिला परिषद कार्य विभाग मंत्री, श्री लखमन रिम्बुई ने कहा कि शासन की सशक्त लोकतान्त्रिक संस्थाएं विकास का आधार होती हैं। उन्होंने यह आशा

व्यक्त की कि यह आउटरीच कार्यक्रम मेघालय और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों के स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा ।

उदघाटन समारोह के बाद निम्नलिखित विषयों पर पेनल चर्चाएँ हुईं : (i) भारत की संसद और जमीनी स्तर की संस्थाएं : संभावनाएं और चुनौतियाँ - नेतृत्व का प्रथम सोपान (ii) उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थानीय निकायों के नेतृत्व में जनजातीय कल्याण और (iii) उत्तर-पूर्वी राज्यों के प्राकृतिक संसाधन और इनके संरक्षण में स्थानीय और परंपरागत निकायों की भूमिका ।

मेघालय सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों के स्थानीय निकायों के लगभग 115 सदस्यों ने उपर्युक्त कार्यक्रम में भाग लिया । इसके अलावा सभी उत्तर पूर्वी राज्यों से अनेक प्रतिभागी वेबलिनक के माध्यम से ऑनलाइन इस कार्यक्रम में शामिल हुए ।

आज आयोजित समापन सत्र के बाद यह कार्यक्रम संपन्न हो गया ।

आउटरीच कार्यक्रम लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य पूरे देश में स्थानीय निकायों में सुशासन को बढ़ावा देना है । इस कार्यक्रम के माध्यम से निचले स्तर से शीर्ष स्तर तक विभिन्न स्तरों पर कार्यरत लोकतांत्रिक संस्थाओं द्वारा अपनाई जा रही पद्धतियों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाकर लोकतंत्र में भागीदारी को बढ़ावा देने पर बल दिया जा रहा है। पहले आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन 8 जनवरी 2021 को देहरादून में किया गया था जिसमें 445 पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था

और 40,000 पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी वेबलिंग के माध्यम से ऑनलाइन इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे ।

बाद में श्री बिरला ने प्रेस को संबोधित किया ।

इससे पहले, 25 फरवरी, 2021 को श्री बिरला ने मेघालय विधान सभा के सदस्यों को संबोधित किया । इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, श्री बिरला ने कहा कि संसद से लेकर राज्यस विधानमंडलों और स्था नीय निकायों तक सभी संस्थाओं को आपसी समन्वय और सहभागिता से कार्य करना चाहिए और अपनी सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को एक-दूसरे के साथ साझा करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब हमारे कार्यों से समाज की अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भला हो। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि संवाद, वाद-विवाद और चर्चा से इस लक्ष्य को प्राप्ते किया जा सकता है।

कोविड-19 महामारी के दौरान लोक सभा में हुए विधायी कार्य के बारे में जानकारी देते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि संसद ने महामारी के दौरान कार्य करके जनता को सकारात्मक संदेश दिया और उनका विश्वास बढ़ाया। उन्होंने महामारी के दौरान मेघालय विधान सभा द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका की भी सराहना की ।

श्री ओम बिरला ने मेघालय विधान सभा के नए भवन के निर्माण स्थल का दौरा भी किया। और इस संबंध में संसद की ओर से विधान सभा को सभी संभव सहायता और सहयोग दिए जाने का आधवासन दिया ।

**LOK SABHA SPEAKER INAUGURATES OUTREACH & FAMILIARISATION PROGRAMME FOR LOCAL BODIES OF MEGHALAYA AND OTHER NORTH-EASTERN STATES IN SHILLONG**

...

**DISTRICT COUNCILS, WHICH FUNCTION AS MINI LEGISLATIVE BODIES, SHOULD ENSURE EXECUTIVE ACCOUNTABILITY: LOK SABHA SPEAKER**

...

**ACT EAST POLICY HAS OPENED UP IMMENSE POSSIBILITIES FOR DEVELOPMENT OF THE NORTH EAST: SHRI OM BIRLA**

...

**SHRI BIRLA CALLS FOR USE OF ICT AND INNOVATION TOOLS IN LOCAL BODIES TO MAKE THEIR ADMINISTRATION MORE TRANSPARENT AND ACCOUNTABLE**

...

**LOK SABHA SPEAKER URGES STAKEHOLDERS OF DEMOCRATIC INSTITUTIONS TO SOLVE ALL PROBLEMS CONSTRUCTIVELY THROUGH DISCUSSION AND DIALOGUE.**

...

**NATIONAL INTEGRATION IS THE CORE VALUE THAT WE MUST ALL PRIORITISE IN OUR THINKING AND ACTIONS: CHIEF MINISTER, MEGHALAYA**

...

**Shillong, 26 February, 2021:** Lok Sabha Speaker, Shri Om Birla, who arrived in Shillong on 25 February 2021, inaugurated the Outreach and

Familiarisation Programme for the Local Bodies of the State of Meghalaya and the other North Eastern States today.

Dr. Conrad K. Sangma, Chief Minister, Meghalaya; Shri Rameshwar Teli, Union Minister of State, Ministry of Food Processing Industries; Shri Metbah Lyngdoh, Speaker, Meghalaya Legislative Assembly and Shri Lakhmen Rymbui, Minister for District Council Affairs Department, Government of Meghalaya also graced the function.

Inaugurating the programme, Lok Sabha Speaker Shri Om Birla said that the broad objective of the Programme is to ensure that accountability of the executive is not only ensured in Parliament and Assemblies but at the grassroots level also. In this regard, Shri Birla stressed that Autonomous District Councils which function as mini legislative bodies should ensure executive accountability through discussions and dialogue.

Shri Birla observed that initiatives like “Vocal for Local” will boost local area development. He felt that Aatmanirbhara Bharat can only be possible when we opt for “Vocal for Local”. Recalling the vision of Mahatma Gandhi, Lok Sabha Speaker said that when every village will be Aatmanirbhara, India will be Aatmanirbhara. The Speaker also said that our Act East policy has opened up immense possibilities for the development of the North East and North Eastern States should tap the opportunities to the maximum.

Shri Birla called for extensive use of ICT and innovation tools in local bodies to make their administration more transparent, accountable and accessible. The Speaker further said that panchayati raj institutions and District Councils should deliberate upon developmental programmes encompassing concepts of inclusive growth, co-operation and collectivism and address the issues facing people.



Highlighting the imperative of balancing regional aspirations and national integration, Shri Birla said that both are important for strengthening our democracy. He urged the stakeholders of democratic institutions to solve all problems constructively through discussion and dialogue.

Observing that national integration is the core value that we must all prioritise in our thinking and actions, Meghalaya Chief Minister Dr. Conrad K. Sangma emphasised on the need for funding to District Councils under Finance Commission devolution, inclusion of District Councils under Anti-Defection law, inclusion of Khasi, Garo and other languages in the 8th Schedule of the Constitution, inclusion of information on North Eastern tribes and culture in national syllabus for school children and setting up of a Presidential Retreat in the North-East. He thanked Lok Sabha Speaker for having decided to hold the Programme in Shillong and providing opportunities to the representatives of local bodies in Meghalaya and other North Eastern States to share their experiences.

Union Minister of State, Ministry of Food Processing Industries, Shri Rameswar Teli said that Panchayat Raj Institutions and other local bodies are powerful vehicles in nation-building. He emphasized that traditional values of democracy must be preserved for further deepening of democratic ethos at grassroots levels.

Speaker, Meghalaya Legislative Assembly, Shri Metbah Lyngdoh stressed on the importance of maximising self-governance to not only empower people but also to take governance to the doorsteps of the last mile of the population. He also emphasized on the empowering PRIs and ADCs at the grassroots level so that the grievances and aspirations of the people could be accommodated in deliberations of such bodies.

Minister for District Council Affairs Department, Government of Meghalaya Shri Lakhmen Rymbui was of the view that strong democratic institutions of governance are at the centre of development. He hoped that the Outreach Programme would prove to be immensely beneficial for the representatives of local bodies in Meghalaya and other North-Eastern States.

The inaugural function was followed by panel discussions on the following themes: (i) Indian Parliament and Grass Root level Institutions: Potential and Challenges – Stepping stone towards leadership; (ii) Leadership of Local bodies for the tribal welfare in the North Eastern States, and (iii) Natural resources of North Eastern States and role of local and traditional bodies in preservation and conservation.

Around 115 Members of the Local Bodies of North Eastern States, including Meghalaya, physically attended the above-mentioned programme. In addition, a large of participants from all of the North Eastern States were connected to the programme 'online via weblink'.

The Programme concluded with the Valedictory Session today.

The Outreach Programme is a unique initiative of the Lok Sabha Speaker Shri Om Birla to bring about the good governance in the of the local bodies across India. The focus is on enhancing participatory democracy through greater awareness of the procedures and processes followed by democratic institutions functioning at various levels from the grassroots to the apex level. The first such Outreach Programme, organized in Dehradun on 08th January 2021, was physically attended by 445 Panchayat representatives and

approximately 40,000 Panchayat Representatives & officials were also connected to the programme 'online via weblink'.

Later, Shri Birla addressed the Press.

Earlier on 25 February 2021, Shri Birla had addressed the Members of the Meghalaya Legislative Assembly.

Speaking on the occasion, Shri Birla said that democratic institutions, from Parliament to State Legislatures and Local Bodies should work in harmony and share their best practices for greater efficacy. He emphasized that democracy can be successful only when it benefits the last person standing on the periphery. He emphasised that dialogue, debate and discussion are the tools to achieve the above end.

Recalling the legislative business transacted in Lok Sabha during the Covid-19 pandemic, the Speaker said that Parliament sent a positive message to people and enhanced their confidence by transacting business amidst the pandemic. He also lauded the positive role played by the Meghalaya Legislative Assembly during the pandemic.

Shri Om Birla also visited the construction site of the new building of Meghalaya Legislative Assembly and assured that all possible support and assistance would be provided to the Assembly by the Parliament in this regard.